# मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XVIII अंक 12 मार्च 2023

आज़ादी का अमृत महोत्सव

RESERVE BANK OF INDIA भारतीय रिज़र्व बैंक

एमसीआईआर

## विषयवस्तु



| | खंड | पृष्ठ |
|---|---|---|
| I. | मौद्रिक नीति | 1 |
| II. | विनियमन | 1-2 |
| III. | भुगतान और निपटान प्रणाली | 2 |
| IV. | वित्तीय बाज़ार | 2 |
| V. | सरकार का बैंक | 2-3 |
| VI. | विदेशी मुद्रा प्रबंधन | 3 |
| VII. | प्रकाशन | 4 |
| VIII. | जारी आंकड़े | 4 |
| IX. | फॉर्म IV | 4 |



## संपादक की कलम से

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा मार्च 2023 माह के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

संवाद के इस माध्यम से सूचनाएं साझा करने, शिक्षित करने और आप सबसे जुड़े रहने के साथ हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रसारित की जा रही सूचनाओं में तथ्यात्मक सटीकता एवं संगति रहे।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

**योगेश दयाल**
**संपादक**

# I. मौद्रिक नीति

## मौद्रिक नीति समिति की बैठक की समय-सारणी

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडआई के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 मार्च 2023 को यह निर्णय लिया कि 2023-24 के दौरान मौद्रिक नीति समिति की बैठकें निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित की जाएंगी:

| 2023-24 के लिए मौद्रिक नीति समिति की बैठकों की तिथियां | |
|---|---|
| पहला | 3, 5 और 6 अप्रैल 2023 |
| दूसरा | 6-8 जून 2023 |
| तीसरा | 8-10 अगस्त 2023 |
| चौथा | 4-6 अक्तूबर 2023 |
| पाँचवाँ | 6-8 दिसंबर 2023 |
| छठा | 6-8 फरवरी 2024 |

## केंद्रीय बोर्ड की बैठक

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 601वीं बैठक हैदराबाद में श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बोर्ड ने अपनी बैठक में वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थिति तथा वर्तमान वैश्विक भू-राजनीतिक गतिविधियों के प्रभाव सहित संबंधित चुनौतियों की समीक्षा की। इसके अलावा, बोर्ड ने वर्तमान लेखा वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक की गतिविधियों पर चर्चा की। बोर्ड ने लेखा वर्ष 2023-24 के बजट को भी अनुमोदन प्रदान किया।

उप गवर्नर श्री महेश कुमार जैन, डॉ. माइकल देवब्रत पात्र, श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रबी शंकर और केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक यथा श्री सतीश के. मराठे, प्रो. सचिन चतुर्वेदी, श्री पंकज रमणभाई पटेल और डॉ. रवींद्र एच. ढोलकिया ने बैठक में भाग लिया। श्री अजय सेठ, सचिव, वित्तीय कार्य विभाग और डॉ. विवेक जोशी, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग ने भी बैठक में भाग लिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

# II. विनियमन

## पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 2 मार्च 2023 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त कर दिया। आउटसोर्सिंग और अन्य पक्ष के ऐप के माध्यम से डिजिटल ऋण के परिचालन में उचित व्यवहार संहिता संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के उल्लंघन, जिसे सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक माना गया, के कारण कंपनी के सीओआर को निरस्त कर दिया गया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

इसके अलावा, 17 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

## संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक के साथ एमओयू

भारतीय रिज़र्व बैंक और संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक (सीबीयूएई) ने सहकारिता बढ़ाने तथा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में संयुक्त रूप से नवोन्मेष को सक्षम बनाने के लिए 15 मार्च 2023 को आबू धाबी में एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। एमओयू के अंतर्गत, दोनों केंद्रीय बैंक फिनटेक के

फिनटेक के विभिन्न उभरते क्षेत्रों, विशेष रूप से केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (सीबीडीसी) पर सहयोग प्रदान करेंगे तथा सीबीयूएई और भारतीय रिज़र्व बैंक के सीबीडीसी के बीच अंतरपरिचालनीयता की जांच करेंगे। सीबीडीसी के सीमापारीय उपयोग मामले के परीक्षण के इस द्विपक्षीय समझौते से लागत के कम होने, सीमापारीय लेनदेन की दक्षता में वृद्धि होने तथा भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आर्थिक संबंधों के और अधिक मजबूत होने की आशा है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

### 'नए ग्रीनफील्ड डाटा सेंट'

श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 मार्च 2023 को भुवनेश्वर, ओडिशा में "ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर" और 'एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एवं साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान' की स्थापना के लिए आधारशिला रखी।

गवर्नर ने अपने उद्बोधन में पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय क्षेत्र और भारतीय रिज़र्व बैंक की गतिविधियों का समर्थन करने और हाल ही में महामारी से एक सुदृढ़ बहाली में सहायता प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को सराहा। उन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक की भावी गतिविधियों के लिए केंद्रीय बैंकिंग, प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा से जुड़े उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान और क्षमता संवर्धन हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं से समर्थित भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा कंप्यूटिंग अवसंरचना के संवर्धन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

18.55 एकड़ के क्षेत्र में फैला नया डाटा सेंटर और एंटरप्राइज़ कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की जब शुरुआत की जाएगी, तो यह रिज़र्व बैंक और वित्तीय क्षेत्र की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करेगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

### शहरी सहकारी बैंकों के लिए संशोधित नियामक ढांचा

1 दिसंबर 2022 को 'संशोधित नियामक ढांचा - विनियामक उद्देश्यों के लिए शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का वर्गीकरण' पर शहरी सहकारी बैंकों से संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार, रिज़र्व बैंक ने 28 मार्च 2023 को निर्णय लिया कि 'शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित नियामक ढांचा – निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता' से संबंधित अनुदेश 31 मार्च 2023 से प्रभावी होंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

## III. भुगतान और निपटान प्रणाली

### डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023

श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 मार्च 2023 को डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह (डीपीएडब्ल्यू) 2023 के अवसर पर 'हर पेमेंट डिजिटल' अभियान का शुभारंभ किया। डीपीएडब्ल्यू 2023 को 6 से 12 मार्च 2023 तक मनाया गया। अभियान का विषय "डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ" (Adopt digital payments and Also teach others) है।

डीपीएडब्ल्यू 2023 के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों ने जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए, जो भारतीय जी20 प्रेसीडेंसी के अंतर्गत 'जन भागीदारी' कार्यक्रमों का भी हिस्सा बने। इसी तरह की पहल बैंक और गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों द्वारा भी की गई। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

## IV. वित्तीय बाज़ार

### स्थायी चलनिधि सुविधा

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थिति की समीक्षा पर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 मार्च 2023 को यह निर्णय लिया कि 31 मार्च 2023 को एकल प्राथमिक व्यापारियों के लिए प्रचलित रेपो दर पर स्थायी चलनिधि सुविधा के अंतर्गत ₹5,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। विशेष व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त राशि का पुनर्भुगतान 5 अप्रैल 2023 को या उससे पहले किया जाएगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

### एनजीएनएफ़ का वित्तीय कार्यनिष्पादन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 मार्च 2023 को 9,659 कंपनियों, जिनके द्वारा 2019-20 से 2021-22 तक तीन लेखा वर्षों के लिए भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) प्रारूप में रिपोर्ट किया गया, के लेखापरीक्षित वार्षिक खातों पर आधारित वर्ष 2021-22 के दौरान गैर-सरकारी गैर-वित्तीय (एनजीएनएफ) प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के वित्तीय कार्य-निष्पादन से संबंधित आंकड़े जारी किए। इन कंपनियों की चुकता पूंजी (पीयूसी) ₹5,59,510 करोड़ थी, जो मार्च 2022 में एनजीएनएफ़ पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कुल पीयूसी का 30.1 प्रतिशत थी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

## V. सरकार का बैंकर

### भारत सरकार की अर्थोपाय अग्रिम सीमा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से दिनांक 29 मार्च 2023 को यह निर्णय लिया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली छमाही (अप्रैल 2023 से सितंबर 2023) के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा ₹1,50,000 करोड़ होगी। जब भारत सरकार अर्थोपाय अग्रिम सीमा के 75 प्रतिशत का उपयोग कर लेगी तब भारतीय रिज़र्व बैंक नए बाजार ऋणों को जारी कर सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के परामर्श से किसी भी समय, सीमा को संशोधित करने की छूट अपने पास रखता है। अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर निम्नानुसार होगी:

i) अर्थोपाय अग्रिम: रेपो दर

ii) ओवरड्राफ्ट: रेपो दर से दो प्रतिशत अधिक

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

### मार्च 2023 लेनदेन की रिपोर्टिंग

रिज़र्व बैंक ने 16 मार्च 2023 को एजेंसी बैंकों को सूचित किया की वे 24 फरवरी 2022 को जारी परिपत्र का संदर्भ लें, जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बैंक के प्राप्तकर्ता/नोडल/फोकल पॉइन्ट शाखाओं में केंद्रीय सरकार के लेनदेनों के लेखांकन और रिपोर्टिंग के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया के बारे में बताया गया था।। तदनुसार, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि मार्च 2023 महीने के लिए अवशिष्ट लेनदेनों को बंद करने की तिथि 10 अप्रैल 2023 निर्धारित की जाए। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

### दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए निर्गम कैलेंडर

संस्थागत और खुदरा निवेशकों को उनके निवेश की कार्यकुशल योजना बनाने और सरकारी प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता एवं स्थिरता प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से दिनांक 29 मार्च 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली छमाही (01 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2023) के लिए सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए ₹8,88,000 करोड़ की राशि का सांकेतिक कैलेंडर अधिसूचित किया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

## ख़ज़ाना बिलों की नीलामी का कैलेंडर

दिनांक 29 मार्च 2023 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से जून 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय ख़ज़ाना बिलों के निर्गम के लिए ₹4,16,000 करोड़ की राशि अधिसूचित की है। भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक के पास, भारत सरकार की आवश्यकताओं, उभरती बाजार स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर ख़ज़ाना बिलों की अधिसूचित राशि और समय-सारणी में बाजार को विधिवत सूचना देने के बाद संशोधन करने की छूट होगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

# VI. विदेशी मुद्रा प्रबंधन

## अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2023 को दिसंबर 2022 के अंत के 'भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति' से संबंधित आंकड़े जारी किए। दिसंबर 2022 के अंत में भारत की आईआईपी की मुख्य विशेषताएं हैं-

i) अक्तूबर-दिसंबर 2022 के दौरान भारत पर अनिवासियों के निवल दावों में 12.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई और दिसंबर 2022 के अंत में यह 374.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

ii) निवल दावों में कमी भारतीयों की विदेशी देयताओं में वृद्धि (16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की तुलना में भारतीय निवासियों की समुद्रपारीय वित्तीय आस्तियों में उच्चतर वृद्धि (28.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के कारण थी।

iii) 2022-23 की तीसरी तिमाही के दौरान भारतीय निवासियों की विदेशी आस्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से आरक्षित आस्तियों में 30.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि के कारण हुई थी, जिसमें पिछली तिमाही में 56.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई थी।

iv) दिसंबर 2022 के अंत तक भारत की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय आस्तियों में आरक्षित आस्तियों का हिस्सा 64.3 प्रतिशत था।

v) भारत की विदेशी देयताओं में वृद्धि के लिए व्यापार क्रेडिट और ऋण प्राथमिक योगदानकर्ता थे।

vi) अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में मूल्य निर्धारण करने पर अन्य मुद्राओं की तुलना में रुपये की विनिमय दर में भिन्नता ने देयताओं में परिवर्तन को प्रभावित किया, क्योंकि तिमाही के दौरान रुपये में 1.49 प्रतिशत की गिरावट आई।

vii) कुल बाह्य देयताओं में ऋण देयताओं का हिस्सा एक तिमाही पहले के 49.8 प्रतिशत और एक वर्ष पहले के 48.4 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर 2022 के अंत में 50.2 प्रतिशत हो गया।

viii) दिसंबर 2022 में भारत की अंतरराष्ट्रीय आस्तियां भारत की अंतरराष्ट्रीय देयताओं की 70.0 प्रतिशत रहीं, जबकि एक वर्ष पहले यह 72.5 प्रतिशत थी।

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

## भुगतान संतुलन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2023 को 2022-23 की तीसरी तिमाही (अक्तूबर-दिसंबर) के लिए भारत के भुगतान संतुलन (बीओपी) से संबंधित गतिविधियों के आंकड़े जारी किए। भुगतान संतुलन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं -

i) भारत का चालू खाता घाटा 2022-23 की तीसरी तिमाही में घटकर 18.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 2.2 प्रतिशत) रह गया, जो 2022-23 की दूसरी तिमाही में 30.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 3.7 प्रतिशत) और एक वर्ष पहले 22.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 2.7 प्रतिशत) था।

ii) वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही में कम चालू खाता घाटा का मुख्य कारण, सुदृढ़ सेवाओं और निजी अंतरण प्राप्तियों के साथ वस्तु व्यापार घाटे में 2022-23 की दूसरी तिमाही के 78.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में कम होकर 72.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर होना था।

iii) सॉफ्टवेयर के बढ़ते निर्यात, कारोबार और यात्रा सेवाओं के कारण सेवा निर्यात में वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर 24.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। निवल सेवा प्राप्तियों में क्रमिक रूप से और वर्ष-दर-वर्ष आधार पर दोनों रूप में वृद्धि हुई।

iv) प्राथमिक आय खाते से निवल व्यय, जो मुख्य रूप से निवेश आय भुगतान को दर्शाता है, एक वर्ष पहले के 11.5 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 12.7 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।

v) निजी हस्तांतरण प्राप्तियां, जो मुख्य रूप से समुद्रपार कार्यरत भारतीयों द्वारा प्रेषण का प्रतिनिधित्व करती हैं, 30.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर थीं, जो एक वर्ष पहले के स्तर से 31.7 प्रतिशत अधिक है।

vi) वित्तीय खाते में निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक वर्ष पहले के 4.6 बिलियन अमरीकी डॉलर से घटकर 2.1 बिलियन अमरीकी डॉलर रह गया।

vii) 2021-22 की तीसरी तिमाही में 5.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बहिर्वाह की तुलना में निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अंतर्वाह दर्ज किया गया।

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

## एफ़डीआई का वित्तीय कार्यनिष्पादन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2023 को 2,206 कंपनियों, जिन्होंने 2019-20 से 2021-22 तक तीन लेखा वर्षों के लिए भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) प्रारूप में रिपोर्ट किया, के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा के आधार पर 2021-22 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) कंपनियों के वित्तीय कार्यनिष्पादन से संबंधित आंकड़े जारी किए। इन कंपनियों की चुकता पूंजी (पीयूसी) 5,04,271 करोड़ रुपये थी, जो भारतीय प्रत्यक्ष निवेश कंपनियों की विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों की रिज़र्व बैंक की वार्षिक गणना के 2021-22 दौर में रिपोर्ट की गई एफडीआई कंपनियों के कुल पीयूसी का 54.5 प्रतिशत था।

मॉरीशस, सिंगापुर और यूएसए से प्रत्यक्ष निवेश वाली कंपनियों का प्रतिदर्श कंपनियों में लगभग आधा हिस्सा था। एफ़डीआई के वित्तीय कार्यनिष्पादन की मुख्य बातें निम्नानुसार है-

i) एफडीआई कंपनियों ने 2021-22 में व्यापक सुधार देखा क्योंकि कोविड-19 महामारी का प्रभाव कम हो गया और आर्थिक गतिविधि में तेजी आई; प्रतिदर्श कंपनियों की बिक्री में 29.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई (पिछले वर्ष में 2.0 प्रतिशत की वृद्धि)।

ii) बिक्री में वृद्धि को पूरा करने के लिए परिचालन व्यय में वृद्धि हुई; कुल व्यय की तुलना में कच्चे माल की लागत का अनुपात बढ़कर 51.1 प्रतिशत (पिछले वर्ष में 47.0 प्रतिशत) हो गया।

iii) एफडीआई कंपनियों द्वारा, उनके कुल व्यय में 1.35 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ, रॉयल्टी भुगतान, में 2021-22 में 33.4 प्रतिशत (पिछले वर्ष में 19.7 प्रतिशत) की वृद्धि हुई; कुल व्यय में अनुसंधान और विकास की हिस्सेदारी 0.11 प्रतिशत थी।

iv) प्रतिदर्श कंपनियों के परिचालन लाभ में 2021-22 के दौरान 21.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई; विनिर्माण कंपनियों ने अपने परिचालन लाभ मार्जिन को बनाए रखा, जिसमें सेवा क्षेत्र के लिए मामूली गिरावट आई।

v) समग्र स्तर पर, लीवरेज (ऋण की तुलना में इक्विटी अनुपात के संदर्भ में मापा जाता है) में मामूली सुधार हुआ।

vi) प्रतिदर्श कंपनियों ने करीब 36 प्रतिशत नई निधि का इस्तेमाल स्थिर पूंजी निर्माण में किया। गैर-चालू निवेश, इन्वेंट्री और प्राप्य राशियाँ 2021-22 के दौरान धन के अन्य प्रमुख उपयोग थे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

## VII. प्रकाशन

### आरबीआई बुलेटिन

रिज़र्व बैंक ने अपने मासिक बुलेटिन का मार्च 2023 अंक 21 मार्च 2023 को जारी किया। इस बुलेटिन में पांच भाषण, पांच आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं।

प्रकाशित वे पांच आलेख हैं:

i) अर्थव्यवस्था की स्थिति : वैश्विक संवृद्धि जहाँ पक्के तौर पर धीमी हो रही है या 2023 में एक तरह से मंदी में प्रवेश करने के लिए तैयार दिखती है और वैश्विक वित्तीय बाजार ऊहापोह की स्थिति में है, चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के बाद से सतत गति के साथ, जितना सोचा गया था उसकी तुलना में भारत, मजबूती के साथ महामारी काल से बाहर आया है। आपूर्ति पक्ष में, कृषि मौसमी वृद्धि की अवस्था में है, उद्योग संकुचन से बाहर निकल रहा है और सेवाओं ने गति बनाए रखी है। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति उच्च बनी हुई है और मूल मुद्रास्फीति, इनपुट लागतों में स्पष्ट नरमी के बावजूद अधिक बनी हुई है।

ii) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक: एकीकरण विधि मायने रखती है

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) संकलन की वर्तमान पद्धति में अखिल भारतीय समग्र सूचकांक पर पहुंचने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और क्षेत्रों के सूचकांकों का एकीकरण शामिल है। एकीकरण की समान क्षैतिज पद्धति का पालन करके राष्ट्रीय उप-समूह और समूह स्तर के सूचकांक भी प्राप्त किए जाते हैं। परिणामस्वरूप, आइटम-स्तरीय एकीकरण के माध्यम से अखिल भारतीय सूचकांकों (उप-समूह/समूह/समग्र) को प्राप्त करने का कोई भी प्रयास प्रकाशित सूचकांकों से भिन्न हो सकता है, विशेष रूप से जब कीमतों की अनुपलब्धता या रियायती वस्तुओं के प्रावधान की स्थितियाँ हों जहाँ प्राइस कोट शून्य हो सकते हैं, जैसा कि जनवरी-फरवरी 2023 में हुआ था। यह आलेख, इस संदर्भ में, सीपीआई के संकलन में अपनाई गई एकीकरण पद्धति, प्रकाशित और उपयोगकर्ता व्युत्पन्न सीपीआई मुद्रास्फीति के बीच देखे गए विचलन की सीमा और मुद्रास्फीति के आकलन में इस तरह के विचलन को कम करने के व्यवहार्य तरीकों पर विमर्श प्रस्तुत करता है।

iii) भारतीय अर्थव्यवस्था 2020-21 के वित्तीय स्टॉक और निधियों का प्रवाह

आलेख वर्ष 2020-21 के लिए 'किससे-किसको' (एफ़डबल्यूटीडबल्यू) के आधार पर संस्थागत क्षेत्रों अर्थात, वित्तीय निगम; गैर-वित्तीय निगम; सामान्य सरकार; गैर-लाभकारी संस्थानों को सेवा प्रदान करने वाले परिवारों सहित परिवार; और बाकी दुनिया के लिए लिखत-वार वित्तीय स्टॉक और निधियों के प्रवाह (एफ़एसएफ़) पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

iv) भारतीय जीडीपी के लिए जोखिम पर वृद्धि (जीएआर) ढांचे का प्रयोग

यह आलेख जीएआर फ्रेमवर्क का उपयोग करके भारत के लिए जीडीपी वृद्धि के भावी वितरण को प्रभावित करने में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय समष्टि-वित्तीय स्थितियों की भूमिका का विश्लेषण करता है। यह कम संभाव्यता वाली चरम घटनाओं पर प्रकाश डालने में मदद करता है और सामान्येतर जोखिम परिदृश्यों की संभावना को मापने में मदद करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जीएआर बेसलाइन माध्य वृद्धि पूर्वानुमान के बजाय जीडीपी वृद्धि के निम्नतर क्वांटाइल से संबंधित होता है।

v) भारत में उप-राष्ट्रीय उधार - राज्य सरकार प्रतिभूति (एसजीएस) दायरे (स्प्रेड) की अस्थिरताएं और निर्धारक

यह आलेख राज्य सरकार की प्रतिभूतियों (एसजीएस) के लिए प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों पर रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए महामारी और नीतिगत उपायों के प्रभाव को रेखांकित करता है। यह जी-सेक और एसजीएस प्रतिफल के बीच संबंधों और प्राथमिक बाजारों में एसजीएस के मूल्य निर्धारण करने वाले कारकों का अध्ययन करता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

## VIII. जारी आंकड़े

मार्च 2023 माह के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े निम्नानुसार हैं:

| क्रम सं. | शीर्षक |
|---|---|
| 1. | भारतीय रिज़र्व बैंक- देयताएं और आस्तियां |
| 2. | भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन |
| 3. | भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर की बिक्री/खरीद |
| 4. | भारतीय रिज़र्व बैंक के बकाया वायदा (मिलियन अमेरिकी डॉलर ) का परिपक्वता ब्रेकडाउन (अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा) |
| 5. | भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं |
| 6. | मुद्रा स्टॉक उपाय |
| 7. | बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन- फरवरी 2023 |
| 8. | भारत के विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में परिवर्तन के स्रोत |
| 9. | फरवरी 2023 के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश |
| 10. | केंद्र सरकार के खाते एक नज़र में |
| 11. | अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार और जमा दरें - मार्च 2023 |


**मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फोर्मेशन रिव्यू के स्वामित्व और अन्य विवरणों से संबंधित ब्योरे**

**फॉर्म IV**

| | |
|---|---|
| प्रकाशन का स्थान | मुंबई |
| प्रकाशन की अवधि | मासिक |
| संपादक, प्रकाशक और मुद्रक का नाम, | योगेश दयाल |
| राष्ट्रीयता | भारतीय |
| पता | भारतीय रिज़र्व बैंक<br>संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई 400001 |
| उन व्यक्तियों के नाम और पते जो समाचार पत्र के मालिक हैं | भारतीय रिज़र्व बैंक<br>संचार विभाग<br>केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई 400001 |

मैं, योगेश दयाल, एतद्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

ह/-
योगेश दयाल
प्रकाशक का हस्ताक्षर
1 मार्च 2023



**योगेश दयाल** द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।